



19 मिनट	8	24	5 + 1	GS1 • 1 GS2 • 16 GS3 • 18
पढ़ने का समय	मुख्य खबरें	संक्षेप में	MCQS + MAINS	पेपर मिश्रण

01 — आज 2 मिनट में

5 खबरें जो छोड़नी नहीं हैं

1 अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शुक्रवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर लगाए

क्यों ज़रूरी: ट्रम्प प्रशासन ने बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) को भंग करने के उद्देश्य से इसके खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेचेगा 250 बिलियन रुपये के बॉन्ड, CRR में बदलाव

क्यों ज़रूरी: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बाजार से लिक्विडिटी (तरलता) कम करने के लिए ₹250 बिलियन के बॉन्ड की बिक्री की घोषणा की है, क्योंकि बैंकों के लिए कैश रिज़र्व रेशियो (CRR) की आवश्यकता 16 अक्टूबर से 90% से बढ़ाकर 99% होने वाली है।

GS3 • अर्थव्यवस्था

P

3 ECI ने कर्नाटक बल्क फाइलिंग विवाद के बाद मतदाता सूची से नाम हटाने के अनुरोधों को 10 तक सीमित किया

क्यों ज़रूरी: मतदाता सूची की अखंडता और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय: यह GS2 राजनीति (Polity) से संबंधित एक प्रासंगिक विषय है।

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

4 भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में परमाणु ब्लैकमेल के खिलाफ राइट ऑफ रिप्लाई दिया

क्यों ज़रूरी: बहुपक्षीय कूटनीति और आतंकवाद विरोधी अभियान: UN में भारत के रुख पर एक GS2 केस स्टडी।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

M

5 एमपी हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने वाला कानून रद्द कर दिया

क्यों ज़रूरी: राज्य की आरक्षण नीतियों की न्यायिक समीक्षा: संवैधानिक वैधता और समानता पर GS2 केस स्टडी।

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

आज का आँकड़ा

10 अनुरोध

दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान व्यक्तिगत मतदाता विलोपन (voter deletion) अनुरोधों पर कैप।

स्टैटिक से जोड़ें

Representation of the People Act, 1950

यह वोटर लिस्ट के रखरखाव और Section 31 के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। खबर में ECI ने कर्नाटक बल्क फाइलिंग विवाद के बाद मतदाता सूची से नाम हटाने के अनुरोधों को 10 तक सीमित किया।

GS2 · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर लगाए

चर्चा में क्यों: ट्रम्प प्रशासन ने बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) को भंग करने के उद्देश्य से इसके खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है।

याद रखें

- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)।
- मार्को रूबियो: US Secretary of State
- फ्रांसेस्का अल्बनेज़े: ICC से जुड़ी हुई।

मेन्स कोण अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों पर एकपक्षीय प्रतिबंधों के वैश्विक कानून के शासन और बहुपक्षीय सहयोग पर पड़ने वाले निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/134000

GS3 · अर्थव्यवस्था

P

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेचेगा 250 बिलियन रुपये के बॉन्ड, CRR में बदलाव

चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बाजार से लिक्विडिटी (तरलता) कम करने के लिए ₹250 बिलियन के बॉन्ड की बिक्री की घोषणा की है, क्योंकि बैंकों के लिए कैश रिज़र्व रेशियो (CRR) की आवश्यकता 16 अक्टूबर से 90% से बढ़ाकर 99% होने वाली है।

याद रखें

- RBI बॉन्ड बिक्री की राशि: ₹250 बिलियन (\$2.58 बिलियन)।
- बॉन्ड मैच्योरिटी रेंज: फिस्कल 2030 से फिस्कल 2035।
- नई CRR आवश्यकता: दैनिक बैलेंस का 99%।

मेन्स कोण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए बांड बिक्री और वैधानिक तरलता अनुपात (CRR) समायोजन जैसे तरलता प्रबंधन उपकरणों के उपयोग का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/133832

GS2 · राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

ECI ने कर्नाटक बल्क फाइलिंग विवाद के बाद मतदाता सूची से नाम हटाने के अनुरोधों को 10 तक सीमित किया

चर्चा में क्यों: कर्नाटक में हुए एक विवाद के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने एक साथ बड़ी संख्या में फॉर्म 7 (Form 7) जमा किए जाने से रोकने के लिए व्यक्तिगत मतदाता विलोपन अनुरोधों की संख्या पर सीमा तय कर दी है।

याद रखें

- Representation of the People Act, 1950 — यह वोटर लिस्ट के रखरखाव और Section 31 के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- फॉर्म 7 — मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विशिष्ट आवेदन फॉर्म।
- 10 अनुरोध — दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान व्यक्तिगत मतदाता विलोपन (voter deletion) अनुरोधों पर कैप।

मेन्स कोण मतदाता सूची से थोखाधड़ीपूर्ण विलोपन को रोकने और उसकी शुचिता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/133624

GS2 · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

M

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में परमाणु ब्लैकमेल के खिलाफ राइट ऑफ रिप्लाई दिया

चर्चा में क्यों: भारत के कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट (Conference on Disarmament) में स्थायी मिशन के अनमोल शेर सिंह बेदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति में 'राइट ऑफ रिप्लाई' (Right of Reply) दिया।

याद रखें

- अनमोल शेर सिंह बेदी — कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट (Conference on Disarmament) में भारत के परमानेंट मिशन के प्रतिनिधि।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा की फर्स्ट कमेटी (First Committee) — यह कमेटी निरस्त्रीकरण (disarmament) और हथियारों के नियमन के लिए जिम्मेदार है।
- ऑपरेशन सिंदूर — 22 अप्रैल, 2025 को हुए हमले के जवाब में मई 2025 में संचालित किया गया।

मेन्स कोण सीमावर्ती देशों से होने वाले सीमा पार आतंकवाद और परमाणु दबाव का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करने की भारत की रणनीति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/133758

एमपी हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने वाला कानून रद्द कर दिया

चर्चा में क्यों: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 को रद्द कर दिया है।

याद रखें

- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट: न्यायिक निकाय जिसने 2019 के संशोधन अधिनियम (Amendment Act) को असंवैधानिक घोषित किया।
- OBC आरक्षण में वृद्धि: विवादित संशोधन के जरिए इस कोटा को 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव रखा गया था।
- अनरिज़र्व कोटा: कोर्ट ने आदेश दिया कि खाली पदों में से 13% पदों को अनरिज़र्व उम्मीदवारों से भरा जाए।

मेन्स कोण आरक्षण कोटा में राज्य-स्तरीय संशोधनों की संवैधानिक वैधता और अवसर की समानता के सिद्धांत पर उनके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/133635

TGSPDCL ने घरेलू ग्राहकों से PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम

चर्चा में क्यों: TGSPDCL, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा दे रहा है, जिसके तहत 3 kWp सिस्टम के लिए अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी दी जा रही है।

याद रखें

- PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए सब्सिडी प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की योजना।
- 3 kWp रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी दी जाती है।
- तेलंगाना सरकार ने 15 नवंबर, 2025 को 20.33 लाख घरों के लिए 4,066 MW की मंजूरी दी।

मेन्स कोण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी को दूर करने और साथ ही टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रणालियाँ किस प्रकार सहायक हो सकती हैं, चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/134091

केरलम में पानी की कमी दूर करने के लिए डिसेलिनेशन प्लांट पर विचार

चर्चा में क्यों: केरल की UDF सरकार पानी की कमी को दूर करने के लिए केरल तट के किनारे डिसेलिनेशन प्लांट (Desalination plants) स्थापित करने पर विचार कर रही है।

याद रखें

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT): प्रस्तावित डिसेलिनेशन प्लांट (desalination plant) के संबंध में चर्चा में शामिल संस्था।
- प्रस्तावित प्लांट क्षमता: 10 mld (मिलियन लीटर प्रति दिन)।
- प्रस्तावित प्लांट की लागत: ₹215 करोड़।

मेन्स कोण भारत के तटीय क्षेत्रों में जल संकट के समाधान के रूप में विलवणीकरण (desalination) की व्यवहार्यता और इसके पर्यावरणीय निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/134101

राजनाथ सिंह ने तेजस, ध्रुव और आकाश में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर

चर्चा में क्यों: तरंग शक्ति 2026 वायु अभ्यास के दौरान, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस और आकाश जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म में आत्मनिर्भरता का आह्वान किया।

याद रखें

- तेजस, ध्रुव, रुद्र, प्रचंड, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और आकाश को आत्मनिर्भरता के लिए प्रमुख स्वदेशी प्लेटफॉर्म के रूप में पहचाना गया है।
- तरंग शक्ति 2026 का आयोजन जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन में किया गया।
- इस अभ्यास में 32 ऑब्ज़र्वर देशों (observer nations) ने भाग लिया।

मेन्स कोण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण और 'सेंसिंग की गति' (speed of sensing) के महत्व की चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/134011

GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल

मिजोरम सरकार ने ₹19.19 करोड़ के केंद्रीय आवंटन का उपयोग करके जनगणना 2027 (Census 2027) को पूरा करने वाला पहला राज्य बनने की योजना की घोषणा की है

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · सामाजिक न्याय · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुप्रीम कोर्ट केस में 124 पूर्व अधिकारियों ने वोटिंग में धांधली के आरोपों के खिलाफ ECI का बचाव किया

18 राज्यों और 2 UTs में 55 परसेंट जुवेनाइल केस अभी भी पेंडिंग

कर्नाटक ने सेंटर से मांग की कि दिल और किडनी की दवाओं के दाम भी कंट्रोल करें

भारत की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनीं डॉ. कोय्याला रुथ जॉन पॉल

ग्रीन कार्ड सस्पेंशन: ट्रंप प्रशासन ने इंफोसिस, TCS और माइक्रोसॉफ्ट सहित आठ कंपनियों को ग्रीन कार्ड प्रोग्राम से निलंबित कर दिया।

कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब में अकेले रहने वाले माता-पिता में मानसिक तनाव

भारत-इथियोपिया सहयोग: भारत ने इथियोपिया में AI, स्पेस और India Stack पर ध्यान केंद्रित करते हुए 220 से अधिक प्रोजेक्ट्स और 70,000 छात्रों को समर्थन दिया है।

गृह लक्ष्मी योजना: बैंकों को बिना सहमति के लोन या ब्याज के निपटान के लिए ₹2,000 की मासिक किस्तों को ऑटो-डेबिट (auto-debit) करने से रोकने का आदेश दिया गया है।

दिल्ली मेट्रो: सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक सुरक्षा और यात्रियों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पूर्ण प्रतिबंध (complete prohibition) के खिलाफ फैसला सुनाया।

रिट ऑफ मैडमस: बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को 14 निकायों (bodies) में रिक्तियों को भरने के लिए मजबूर करने हेतु PIL दायर की गई।

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा

फॉरेक्स डेरिवेटिव्स: RBI ने कैसिल किए गए रुपया-लिंकड कॉन्ट्रैक्ट्स की रीबुकिंग पर रोक लगा दी है और हेजिंग थ्रेशोल्ड (hedging threshold) को घटाकर \$5 मिलियन कर दिया है।

US सरकार ने इंफोसिस, TCS, विप्रो और HCLTech को PERM प्रोग्राम से हटाया

वायनाड बनेगा इंडिया का पहला ई-वेस्ट-फ्री मॉडल डिस्ट्रिक्ट, 1 नवंबर 2026 का लक्ष्य

साइबर अपराधियों को अब AI से देंगे सबक, असली दिखने वाले बॉट्स से करेंगे ठगना

महाराष्ट्र में दूध की शुद्धता पर नज़र, टैग्ड जानवरों तक ट्रेस होगा दूध

OpenAI और Anthropic के अफसर AI से होने वाले खतरों पर कर रहे चर्चा

तेल आयात: सितंबर में Brent crude की कीमतें \$100 से अधिक होने के बावजूद, भारत ने प्रतिदिन 5.26 मिलियन बैरल तेल आयात किया।

रिलायंस IPO: Reliance और Jio ₹10.3 लाख करोड़ का IPO तैयार कर रहे हैं, जो संभावित रूप से भारत की अब तक की सबसे बड़ी लिस्टिंग (listing) हो सकती है।

बाज़ार में उतार-चढ़ाव: सितंबर 2026 में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और FII की बिकवाली के कारण Nifty 50 और Nifty 500 में गिरावट दर्ज की गई।

महाराष्ट्र में सूखे और El Nino से 2026 में कम हो सकता है सुक्रोज

रेलवे एक्ट: सार्वजनिक उपद्रव (public nuisance) को रोकने के लिए, स्पीकर मोड पर ऑडियो बजाने वाले यात्रियों पर ₹1,000 का जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।

बांस का बागान: मणिपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अफीम की खेती के लिए साफ की गई 255 हेक्टेयर जमीन पर बांस लगाएगा।

फॉर्म 7 आवेदन: बल्क डिलीशन (bulk deletions) के आरोपों के बीच कर्नाटक में चार दिनों में 19,376 आवेदनों की भारी संख्या दर्ज की गई।

1 RBI के forex derivatives पर नए नियमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. Authorised Dealers को रद्द किए गए रुपये से जुड़े forex derivative contracts को रीबुक करने की अनुमति है।
2. बिना अंडरलाइंग एक्सपोजर (underlying exposure) स्थापित किए हेजिंग (hedging) के लिए थ्रेशोल्ड को घटाकर \$5 मिलियन के बराबर कर दिया गया है।
3. \$2 मिलियन के बराबर से अधिक के ट्रांजेक्शन के लिए 10% कैश फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिज़र्व (Foreign Exchange Risk Reserve) आवश्यक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 2 (b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

2 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के रखरखाव के लिए किए गए उपायों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. फॉर्म 7 मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आवेदन है।
2. ECI ने निरंतर अपडेटिंग (continuous updation) के दौरान व्यक्तिगत मतदाता विलोपन अनुरोधों (voter deletion requests) की संख्या 10 तक सीमित कर दी है।
3. ECI ने दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान व्यक्तिगत मतदाता विलोपन (voter deletion) अनुरोधों की सीमा 15 निर्धारित की है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

3 संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) की फर्स्ट कमेटी (First Committee) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह कमेटी हथियारों के नियमन (regulation) और निशस्त्रीकरण (disarmament) के लिए जिम्मेदार है।
2. भारत ने मई 2025 में हुए एक हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) का हवाला दिया।
3. यह बयान कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट (Conference on Disarmament) में भारत के परमानेंट मिशन (Permanent Mission) के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

4 कोर्ट द्वारा आदेशित अनरिजर्व्ड (unreserved) उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले पदों का विशिष्ट प्रतिशत क्या था?

- (a) 50% (b) 14%
(c) 13% (d) 27%

5 भारत वर्तमान में अपने तेल की खरीद के लिए कितने देशों तक पहुँचता है?

- (a) 35 (b) 41
(c) 62 (d) 50

मेन्स अभ्यास

आज एक उत्तर लिखें

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों पर एकपक्षीय प्रतिबंधों के वैश्विक कानून के शासन और बहुपक्षीय सहयोग पर पड़ने वाले निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(9) 5 (10) 7 (11) 8 (12) 2 (13) 1 • 2025



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह टेलीग्राम पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + क्विज़ · हर रविवार साप्ताहिक · हिंदी और अंग्रेज़ी · मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh · satyadheesh.in/upsc/reports

कोई गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक या फॉर्मेट चाहिए? हमें लिखें, हम हर मेल पढ़ते हैं:

contact@satyadheesh.in

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।